Official Spokesman's Statement on the U. S. Missile Attack on Baghdad

The Government of India is against state-sponsored terrorism. We are ourselve victims of state-sponsored terrorism from across the border in the West. We support action against state-sponsored terrorism. On the other hand, we are concerned about the violation of national sovereignty. Such phenomena can affect peace and stability in the West Asian region, where assiduous efforts are on to further the peace process. We have sympathy for the people of Iraq and regret that the civilian population has suffered. We hope that all disputes will be settled peacefully without resort to force.

New Delhi

June 28, 1993.

Expansion of Food Processing Industry

274. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government have assessed the scope for expansion of food processing industry in the country.

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that some firms in multinationals have shown interest in investing in the industry;

(d) if so, the details of the proposals; and

(e) reaction of Government thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) and (b) Studies conducted by various agencies/government organisations in different sectors of food processing industries from time to time indicate good scope for expansion of food processing industries in the country. While same sectoral studies are available for food processing sector, the Ministry under Plan Schemes is providing assistance to State Governments and other institutions and organisations for conducting studies in food processing sector for further development.

(c) to (e) As per the Statement of Industrial Policy of July, 1991 Foreign Companies are permitted to invest in the Food Processing Sector as this would being attendant advantages of technology transfer, marketing expertise, introduction of modern managerial techniques and new possibilities of promotion of export. Foreign companies have shown interest in investing in food processing industries in India and a number of proposals for manufacture of fruits and vegetable products, poultry and egg products, milk products, deep sea fishing and fish processing potable alcohol, beer, snack foods, soft drinks, chewing gums, coca-based products, etc. from foreign companies/NRIs from switzerland, Holland, Germany, USA, Singapore, Finland, Italy, Belgium, Thailand, France, Japan, Denmark, Israel, Hongkong have been approved.

संयुक्त क्षेत्र में प्रसंस्करण-एककों को सहायता

275. **श्री ईश दत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फलों और सब्जियों के लिए फसलोत्तर बुनियादी प्रसंस्करण सुविधायें स्थापित करने सहित गैर सरकारी और संयुक्त क्षेत्र के प्रसंस्करण एककों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न योजनायें तैयार की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं जिन्हें आठवीं योजनावधि के दौरान कार्यान्वित किया जा रहा है। इन स्कीमों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संयुक्त क्षेत्र के

उपक्रमों, सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी/सहायित क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि की फल एवं सब्जियों के लिए प्राथमिक फसलोत्तर प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना सहित फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विकास के लिए इक्विटी/अनुदान के रूप में सहायता देने की व्यवस्था है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष (1992-93) के दौरान फल और सब्जी प्रसंस्करण तथा खुम्बी परियोजनाओं के लिए संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों और सहायित क्षेत्र परियोजनाओं को इक्विटी/सहायता अनुदान के रूप में दी गई सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं **(नीचे देखिए)**

(ग) फल और सब्जी प्रसंस्करण सेक्टर से संबंधित इन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए आठवीं योजना अवधि के दौरान 35.00 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है और फल एवं सब्जी प्रसंस्करण सेक्टर के लिए 1993-94 हेतु 11.00 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	प्राप्तकर्ता का नाम और पता	जारी की गयी राशि	उद्देश्य
1.	मै० आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, हैदराबाद	104.00 लाख रुपये (इक्विटी)	आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और ईस्ट गोदावरी जिलों में संयुक्त क्षेत्र में फल और सब्जी परिसरों की स्थापना के लिये।
2.	मै० पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, चंडीगढ़	13.50 लाख रुपये (इक्विटी)	पंजाब राज्य में संयुक्त सेक्टर में मधुमक्खी पालन परियोजना की स्थापना के लिये।
3.	मै० पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, चंडीगढ़	50.00 लाख रुपये (इक्विटी)	पंजाब राज्य में पटियाला जिले के लालरों में संयुक्त क्षेत्र में 100% निर्यातोन्मुखी एकीकृत खुम्बी परियोजना की स्थापना के लिये।
4.	मै० न्यू इंडिया कल्चरल स्पान एंड मशरूम, ब्रह्मपुर।	6.00 लाख रुपये (सहायता अनुदान)	मै० उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, भुवनेश्वर (उड़ीसा) के साथ उड़ीसा राज्य में सहायित क्षेत्र में स्थान प्रयोगशाला की स्थापना के लिये।